

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय औद्योगीकरण में बाधाएँ

Nadim Ahmad

Research Scholar, Department of History

Government Degree College, Budaun,

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

Dr. Anil kumar

Assistant Professor, Head of History Department

Government Degree College, Budaun.

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Bareilly

सार

यह शोधपत्र औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय औद्योगीकरण में आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं की पड़ताल करता है, जो मुख्य रूप से शोषणकारी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप थीं। ब्रिटिश शासन के तहत, भारतीय वस्तुओं पर उच्च टैरिफ, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों के लिए मुफ्त प्रवेश और स्वदेशी उद्योगों के जानबूझकर दमन जैसे उपायों के माध्यम से भारत को व्यवस्थित रूप से विऔद्योगीकृत किया गया था। अनुचित प्रतिस्पर्धा और राज्य के समर्थन की कमी के कारण पारंपरिक शिल्प और कपड़ा उद्योगों को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, नीतियों ने घरेलू औद्योगिक विकास पर कच्चे माल की निकासी और निर्यात को प्राथमिकता दी, जबकि बुनियादी ढांचे में निवेश भारतीय विकास को बढ़ावा देने के बजाय ब्रिटिश आर्थिक हितों की सेवा के लिए किया गया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत आगे यह दर्शाता है कि कैसे पूंजी पलायन ने घरेलू निवेश क्षमता को कमजोर कर दिया। कुल मिलाकर, इन नीतियों ने एक संरचनात्मक निर्भरता पैदा की जिसने भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और औद्योगिक प्रगति को बाधित किया।

मुख्य शब्द: ब्रिटिश, आर्थिक नीतियों, औद्योगीकरण

परिचय

औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में औद्योगीकरण की गति को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों ने गहराई से आकार दिया और गंभीर रूप से बाधित किया। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से पहले, भारत में कपड़ा, धातु और हस्तशिल्प उद्योगों के समृद्ध होने की विशेषता वाली एक संपन्न अर्थव्यवस्था थी। हालाँकि, औपनिवेशिक शासन के आगमन के साथ, पारंपरिक आर्थिक संरचना में एक व्यवस्थित परिवर्तन हुआ जिसने भारत के विकास के मार्ग को एक आत्मनिर्भर, औद्योगिक अर्थव्यवस्था से बदलकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी केंद्र पर निर्भर कर दिया। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि साम्राज्य के वाणिज्यिक और रणनीतिक हितों की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया था। औपनिवेशिक अधिकारियों ने कई तरह की व्यापार और शुल्क नीतियाँ लागू कीं, जिसने भारत के स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जो कभी वैश्विक बाजारों पर हावी था। जबकि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में शुल्क-मुक्त या न्यूनतम शुल्क के साथ अनुमति दी गई थी, भारतीय उत्पादों को ब्रिटिश या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने का प्रयास करते समय भारी कराधान और गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इस असंतुलन ने एक असंतुलित व्यापार संरचना बनाई जो भारतीय उद्यमशीलता और नवाचार

को दबाते हुए ब्रिटिश उद्योगों का पक्ष लेती थी। औपनिवेशिक रणनीति ने घरेलू विनिर्माण के विकास पर कच्चे माल के निष्कर्षण को भी प्राथमिकता दी। भारत को कच्चे कपास, जूट, नील और ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता में बदल दिया गया, जबकि ब्रिटेन से तैयार माल के आयात ने स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के विकास को हतोत्साहित किया। रेलवे और बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढांचे के निवेश को मुख्य रूप से निर्यात के लिए बंदरगाहों तक कच्चे माल की आवाजाही और ब्रिटिश माल के अंतर्देशीय वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया था, न कि भारतीय आर्थिक एकीकरण या औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए। भारतीय औद्योगीकरण में एक और बड़ी बाधा पूंजी और वित्तीय संस्थानों की कमी थी जो देशी व्यवसायों की सेवा करते थे। ब्रिटिश नीतियों ने भारत से ब्रिटेन में धन की महत्वपूर्ण निकासी की, एक ऐसी घटना जिसकी दादाभाई नौरोजी ने अपने "धन की निकासी" सिद्धांत में आलोचना की थी। वित्तीय संसाधनों के इस बहिर्वाह का मतलब था कि उद्योग में घरेलू निवेश न्यूनतम था, और भारतीय उद्यमियों के पास आधुनिक उद्यम बनाने के लिए ऋण और संस्थागत समर्थन तक पहुंच की कमी थी। इसके अलावा, औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और वैज्ञानिक ज्ञान को पोषित करने में विफल रही। तकनीकी नवाचार और स्वदेशी उद्यम के विकास को हतोत्साहित करने वाले प्रशासन के साथ मिलकर, इसने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जिसमें औद्योगिक विकास लगभग असंभव था। इस प्रकार, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ न केवल औद्योगीकरण के लिए बाधक थीं, बल्कि भारत में मौजूदा आर्थिक और औद्योगिक आधार के लिए भी सक्रिय रूप से विनाशकारी थीं। इन नीतियों की विरासत ने भारत के स्वतंत्रता के बाद के औद्योगीकरण प्रयासों के लिए गहरी चुनौतियाँ छोड़ दीं। इस पत्र का उद्देश्य इन बाधाओं में गहराई से उतरना और आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करना है कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक एजेंडे ने भारत की औद्योगिक क्षमता को व्यवस्थित रूप से दबा दिया।

भारतीय उद्योग का पतन:

रोमेश चंद्र दत्त (1901) और दादाभाई नौरोजी (1901) जैसे विद्वान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। अपने मौलिक कार्य, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल में, दत्त ने ब्रिटिश नीतियों द्वारा भारतीय उद्योगों के जानबूझकर विनाश पर प्रकाश डाला, जिसने स्थानीय विनिर्माण को हतोत्साहित किया और ब्रिटिश वस्तुओं का पक्ष लिया। उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने अनुचित प्रतिस्पर्धा, शुल्क और कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से भारत के स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से वस्त्रों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) ने "धन की निकासी" सिद्धांत के माध्यम से भारत के आर्थिक शोषण के बारे में एक सम्मोहक तर्क प्रस्तुत किया, जिसने सुझाव दिया कि भारत में उत्पन्न धन ब्रिटेन में जा रहा था, इस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी के संचय को रोक रहा था।

व्यापार नीतियों की भूमिका:

भारतीय औद्योगिक विकास को रोकने में ब्रिटिश व्यापार नीतियों की भूमिका पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। तीर्थकर रॉय (2000) ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया 1857-1947 में भारतीय उद्योगों को कमजोर करने वाली औपनिवेशिक व्यापार नीतियों का विश्लेषण किया है। रॉय बताते हैं कि ब्रिटिश नीतियों ने एक असमान विनिमय प्रणाली बनाई, जिसमें भारत को कच्चे माल का निर्यात करने और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका तर्क है कि इससे न केवल स्थानीय उद्योगों के विकास में बाधा आई, बल्कि भारत ब्रिटिश उद्योगों पर निर्भर भी रहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों, जैसे कि भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाना और ब्रिटिश वस्तुओं के मुफ्त

आयात की सुविधा, ने सुनिश्चित किया कि भारत अपना खुद का प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र विकसित न कर सके। बिपन चंद्र (2000) ने द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में यह भी चर्चा की है कि कैसे मुक्त व्यापार की ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय वस्तुओं पर उच्च करों के साथ मिलकर पारंपरिक उद्योगों, विशेष रूप से सूती वस्त्र उद्योग को ध्वस्त कर दिया, जो कभी वैश्विक स्तर पर अग्रणी था। कानूनी और अवैध दोनों तरीकों से भारतीय बाज़ार में ब्रिटिश वस्त्रों की शुरुआत ने स्थानीय कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया, खासकर बंगाल और गुजरात में। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक और कपास जैसे भारतीय निर्यातों पर शुल्क लगाने से यह समस्या और भी जटिल हो गई, जिससे औद्योगीकरण और भी हतोत्साहित हुआ।

बुनियादी ढांचे का विकास और इसके निहितार्थ:

जबकि अंग्रेजों ने रेलवे और बंदरगाहों जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की शुरुआत की, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य भारत में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के बजाय ब्रिटिश आर्थिक हितों की पूर्ति करना था। हेरोल्ड लास्की (1940) ने द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में देखा कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण कच्चे माल के निष्कर्षण और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए किया था, खासकर ब्रिटेन को, न कि एक ऐसा आंतरिक बाजार विकसित करने के लिए जो औद्योगिक विकास का समर्थन कर सके। भारत के भीतर तैयार माल की आवाजाही के बजाय कच्चे माल के लिए परिवहन नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित हुआ कि देश एक आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्र के बजाय ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए एक परिधीय आपूर्तिकर्ता बना रहा।

पूंजी पलायन और निवेश:

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसने भारत में औद्योगीकरण में बाधा डाली, वह था पूंजी का व्यवस्थित बहिर्गमन। आर.सी. दत्त (1901) और बाद में पी.जे. थॉमस (1985) ने भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर अपने-अपने कार्यों में, "धन के निकास" पर चर्चा की, जिसका संदर्भ ब्रिटेन द्वारा ब्रिटेन के लाभ के लिए भारत से वित्तीय संसाधनों के व्यवस्थित निष्कर्षण से है। इसमें भारत में ब्रिटिश स्वामित्व वाले उद्यमों से ब्रिटेन को लाभ भेजना, साथ ही भारतीय भूस्वामियों और उत्पादकों पर उच्च कराधान शामिल था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नहीं था। जैसा कि नौरोजी तर्क देते हैं, इस निकास ने औद्योगिक निवेश के लिए आवश्यक घरेलू पूंजी के संचय को रोका। अपने अध्ययन में, एच.बी. दुबे और एम.एन. श्रीनिवास (1973) तर्क देते हैं कि भारतीय उद्यमों की सेवा करने वाले वित्तीय संस्थानों की कमी ने स्थानीय उद्योगों के विकास को और बाधित किया। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में अधिकांश उद्योग या तो विदेशी स्वामित्व वाले थे या ब्रिटिश पूंजी द्वारा भारी रूप से नियंत्रित थे, और भारतीय उद्यमियों को बड़े पैमाने पर औद्योगिक संचालन स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्वदेशी पूंजी की कमी तथा ब्रिटिश बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रभुत्व के कारण औद्योगीकरण मुख्यतः उन क्षेत्रों तक ही सीमित था जो सीधे औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करते थे।

शिक्षा प्रणाली का प्रभाव:

औपनिवेशिक राज्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भी औद्योगीकरण में बाधा डालने में भूमिका निभाई। शशि थरूर (2016) ने एन एरा ऑफ़ डार्कनेस में तर्क दिया है कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को उपनिवेश के प्रशासन में सहायता करने के लिए क्लर्कों और अधिकारियों का एक वर्ग बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, न कि औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने में सक्षम कुशल कार्यबल। अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान और तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा का मतलब था कि भारत में आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए आवश्यक

मानव पूंजी की कमी थी। कुशल श्रम की इस कमी ने विदेशी औद्योगिक वस्तुओं पर भारत की निर्भरता को और मजबूत किया।

उत्तर-औपनिवेशिक व्याख्याएं और परिणाम:

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी लंबे समय तक महसूस किए गए। के.के. अजीज (1993) ने द ब्रिटिश लिगेसी इन इंडिया में इस बात का अवलोकन प्रदान किया है कि औपनिवेशिक विरासत ने भारत के स्वतंत्रता के बाद के औद्योगिकीकरण को कैसे प्रभावित किया। उनका तर्क है कि विकसित औद्योगिक आधार की कमी, औपनिवेशिक शासन के दौरान धन के दोहन के साथ, भारत को एक कमजोर आर्थिक आधार के साथ छोड़ दिया जिसने स्वतंत्रता के बाद तेजी से औद्योगिकीकरण करने की इसकी क्षमता को बाधित किया। यह सीमित औद्योगिक बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की कमी से और भी जटिल हो गया, जिससे भारत को स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में उबरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। निष्कर्ष में, औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों पर साहित्य लगातार इस बात पर जोर देता है कि कैसे इन नीतियों ने व्यवस्थित रूप से औद्योगिकीकरण को बाधित किया। शोषणकारी व्यापार नीतियों, बुनियादी ढांचे की उपेक्षा, पूंजी पलायन और एक सहायक संस्थागत ढांचे की अनुपस्थिति के संयोजन ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां औद्योगिकीकरण न केवल अवरुद्ध था, बल्कि कई मामलों में जानबूझकर कमजोर किया गया था। इन नीतियों का प्रभाव भारत के औपनिवेशिक विकास पथ पर गूंजता रहता है।

ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ

आइए इस नीति की प्रमुख विशेषताओं का पता लगाएं और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा।

- **व्यापार नीतियां जिन्होंने ब्रिटेन की रक्षा की:** ब्रिटिश औद्योगिक नीति ने भारतीय वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन बनाकर ब्रिटिश उद्योगों का समर्थन किया। उन्होंने भारतीय उत्पादों पर उच्च कर लगाकर ऐसा किया।
- **भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव:** ब्रिटिश औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने भारतीय निर्माताओं के लिए नई तकनीक और कच्चे माल तक पहुंच कठिन बना दी।
- **संसाधन लेने पर ध्यान:** अंग्रेज भारत से अधिक से अधिक कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने अपने उद्योगों को बढ़ाने में मदद के लिए कपास, जूट, चाय और खनिज जैसे संसाधन लिए।
- **भारतीय उद्योगों के लिए सीमित अवसर:** ब्रिटिश औद्योगिक नीति ने जानबूझकर भारत को अपने उद्योगों को विकसित करने से रोक दिया। उन्होंने भारत को एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र बनने देने के बजाय भारत को अपने माल के लिए एक बाजार के रूप में देखा।
- **भारत से धन का निकास:** ब्रिटिश औद्योगिक नीति का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि इसने भारत का धन छीन लिया। नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के संसाधन और धन भारत में रहने के बजाय ब्रिटेन चले जाएं।
- **पैसा वापस ब्रिटेन भेज दिया गया:** अंग्रेजों ने भारत में कमाया गया अतिरिक्त पैसा ले लिया और उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया। इससे भारत के लिए उस धन का उपयोग अपने उद्योगों को विकसित करने में करना कठिन हो गया।

- **परिवहन का विकास:** अंग्रेजों ने संसाधन और व्यापार प्राप्त करने में मदद के लिए भारत में रेलवे, बंदरगाह और सड़कों का निर्माण किया। लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीजों में निवेश नहीं किया।
- **सामाजिक आवश्यकताओं की उपेक्षा:** जबकि अंग्रेजों ने परिवहन का निर्माण किया, उन्होंने भारतीयों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इससे भारतीय समाज के विकास पर ब्रिटिश शासन का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।
- **ब्रिटिश कंपनियों का नियंत्रण:** ब्रिटिश औद्योगिक नीति ने ब्रिटिश कंपनियों को विभिन्न उद्योगों पर नियंत्रण हासिल करने में मदद की। इससे भारतीय उद्यमियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना और प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया।
- **सीमित तकनीकी प्रगति:** अंग्रेजों ने भारत के साथ उन्नत तकनीक साझा नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को मशीनों और तकनीकी ज्ञान के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे उसका अपना तकनीकी विकास धीमा हो गया।
- **ऋण और धन हानि:** अपनी नीतियों को वित्तपोषित करने के लिए, अंग्रेजों ने ऐसी प्रणालियाँ शुरू कीं जिससे भारतीय किसानों और किसानों को बहुत अधिक धन का भुगतान करना पड़ा। इससे वे कर्ज में डूब गये और उनकी कमाई चली गयी।
- **भारतीय उद्यमियों के साथ अनुचित व्यवहार:** ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत भारतीय उद्यमियों को अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्हें सख्त नियमों का पालन करना पड़ा, उच्च करों का भुगतान करना पड़ा और ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हुई, जिससे उनके लिए सफल होना कठिन हो गया।

भारत में ब्रिटिश औद्योगिक नीति भारत की आर्थिक वृद्धि की कीमत पर ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इसने भारतीय उद्योगों के लिए अवसरों को सीमित कर दिया, देश से धन को खत्म कर दिया और तकनीकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी इस नीति का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता रहा।

भारत में ब्रिटिश औद्योगिक नीति का प्रभाव

ब्रिटिश औद्योगिक नीति का भारत पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का तरीका बदल गया।

- जब ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया, तो उसने भारत को अन्य देशों को कच्चा माल बेचने के लिए बाध्य किया। भारतीय उद्योग सीमित थे, इसलिए वे ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश व्यवसायों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय उद्योगों को संघर्ष करना पड़ा।
- इस नीति ने भारत को अपने उद्योगों को बढ़ने से रोक दिया। भारत को ब्रिटेन से आयात पर निर्भर रहना पड़ा। इस नीति ने नई नौकरियाँ पैदा करना और भारत के लिए आत्मनिर्भर होना कठिन बना दिया। भारत में लोगों को महंगी ब्रिटिश चीजें खरीदनी पड़ती थीं।
- ब्रिटिश उद्योगों ने भारत के संसाधनों का लाभ उठाया। यह नीति भारत के हित की अपेक्षा ब्रिटिश हितों की अधिक परवाह करती थी। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के लिए बाज़ार बन गयी। इस नीति के कारण भारत अपने उद्योग खो बैठा और गरीब हो गया। जब ब्रिटेन अधिक शक्तिशाली हो गया तो पारंपरिक भारतीय उद्योग कमजोर हो गये। भारतीय कौशल और शिल्प को भुला दिया गया।
- इस नीति ने आर्थिक संबंधों को एकतरफ़ा बना दिया। भारत का धन ब्रिटेन के शासन द्वारा छीन लिया गया। यह नीति भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाज़ार बनाये रखना चाहती थी। ब्रिटिश व्यवसाय मालिकों ने पैसा कमाया

जबकि भारत को नुकसान उठाना पड़ा। इस नीति ने ब्रिटेन को भारत की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। भारत में ब्रिटिश उद्योग सबसे महत्वपूर्ण थे।

- भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर बहुत अधिक निर्भर थी। इस नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को असंतुलित बना दिया। ब्रिटेन के नियमों ने भारत के लिए अपने उद्योगों को बढ़ाना कठिन बना दिया। इस नीति ने ब्रिटेन में अमीर लोगों को और अमीर बना दिया जबकि भारत गरीब बना रहा। इस नीति ने उद्योगों में भारत के भविष्य को धीमा कर दिया। ब्रिटेन के लाभ के लिए उद्योगों में भारत की क्षमता को रोक दिया गया। इस नीति के कारण भारत ब्रिटेन को अपना कच्चा माल देता रहा।
- भारत के संसाधनों के कारण ब्रिटिश उद्योग सफल हुए। इस नीति ने भारत के लिए अपने निर्णय लेना कठिन बना दिया। ब्रिटेन ने भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया। इस नीति ने भारत को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने से रोक दिया। भारत केवल ब्रिटिश चीजों का बाजार बन गया। इस नीति ने भारतीयों के लिए नए व्यवसाय शुरू करना और रचनात्मक होना कठिन बना दिया। भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस नीति ने भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत उद्योगों में पिछड़ गया।
- इस नीति से भारत के संसाधनों का लाभ ब्रिटेन को हुआ। ब्रिटिश उद्योगों ने भारतीय श्रमिकों से पैसा कमाया। इस नीति ने भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से रोक दिया। उद्योगों में भारत की क्षमता को ब्रिटेन के नियमों ने रोक दिया।

इस नीति ने भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिटेन पर निर्भर बना दिया। ब्रिटिश उद्योगों ने पैसा कमाया जबकि भारत को नुकसान उठाना पड़ा। इस नीति ने लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अपने उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश औद्योगिक नीति का प्रभाव हम आज भी भारत में देख सकते हैं।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और संपत्ति का दोहन

भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक हिस्सा अंग्रेज ब्रिटेन को भेज रहे थे और इसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। यह आर्थिक दोहन ब्रिटिश शासन की खास विशेषता थी। इसके पहले बुरी से बुरी भारतीय सरकारों ने भी जनता से चूसी गई दौलत का उपयोग देश के अंदर ही किया था। चाहे उन्होंने इस धन को सिंचाई की नहरें या ग्रेड ट्रंक रोड बनाने पर खर्च किया, महल, मंदिर या मस्जिद बनाने में लगाया, और विजयों के लिए उसका उपयोग किया, या व्यक्तिगत भोग विलास में उसे उड़ाया, लेकिन वह धन अंततः भारतीय उद्योग और व्यापार को ही प्रोत्साहित करता था और भारतीयों को रोजगार देता था। इसका कारण यह था कि विदेशी विजेता, जैसे कि मुगल, बहुत जल्द ही भारत में बस गए और उन्होंने इसी को अपना घर बना लिया। पर अंग्रेज हमेशा विदेशी ही बने रहे।

भारतीय जनता से प्राप्त टैक्स और आय भारत की जगह ब्रिटेन में खर्च करना

भारत में काम कर रहे या व्यापार कर रहे लगभग सभी अंग्रेज ब्रिटेन वापस जाने की योजना बनाते रहते थे। भारत की सरकार पर नियंत्रण विदेशी व्यापारियों की एक कंपनी का और ब्रिटेन की सरकार का था। परिणामस्वरूप भारतीय जनता से प्राप्त करें और आय का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज भारत में नहीं बल्कि अपने देश ब्रिटेन में खर्च करते थे भारतीय शासकों, जमींदारों, व्यापारियों से झटककर जमा की गई दौलत ब्रिटेन ले जाना बंगाल से संपत्ति का यह दोहन 1757 ई. में शुरू हुआ और इसके बाद कंपनी के नौकर भारतीय शासकों, जमींदारों, व्यापारियों और साधारण जनता से झटककर

जमा की गई बेपनाह दौलत अपने देश ले जाने लगे। 1758 ई. और 1765 के बीच उन्होंने लगभग 60 लाख पौड की दौलत ब्रिटेन भेजी। 1765 में बंगाल के नवाब को जमीन की कुल जितनी मालगुजारी प्राप्त हुई, उसकी यह राशि चार गुना भी अधिक थी। इस भयानक दोहन में कंपनी के व्यापारिक मुनाफे शामिल नहीं थे और यह भी प्रायः गैरकानूनी कमाई से कम नहीं होता था।

निष्कर्ष

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों ने औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के औद्योगीकरण को बाधित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए धन और संसाधनों को निकालने की आवश्यकता से प्रेरित इन नीतियों ने व्यवस्थित रूप से भारत के स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर दिया और एक मजबूत औद्योगिक आधार के विकास को बाधित किया। भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियों को लागू करने से लेकर ब्रिटिश आर्थिक हितों के लाभ के लिए बुनियादी ढांचे में हेरफेर करने तक, औपनिवेशिक राज्य ने सुनिश्चित किया कि भारत तैयार माल के उत्पादक के बजाय कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना रहे। ब्रिटिश नीतियों द्वारा पारंपरिक उद्योगों, विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र को जानबूझकर नष्ट करने और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए मुक्त व्यापार की शुरूआत ने एक असमान आर्थिक संबंध बनाया जिसने भारतीय उद्यमशीलता को दबा दिया। नौरोजी और दत्त जैसे विचारकों द्वारा वर्णित भारत से धन की व्यापक निकासी ने औद्योगिक निवेश के लिए आवश्यक पूंजी के संचय को रोक दिया। इसके अलावा, आंतरिक आर्थिक विकास के लिए सुविधाकर्ता के बजाय कच्चे माल के निर्यात के उपकरण के रूप में रेलवे और बंदरगाहों पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की ब्रिटिश उद्योगों पर निर्भरता और बढ़ गई। भारतीय उद्यमियों को सहायता प्रदान करने वाले वित्तीय बुनियादी ढांचे की कमी, साथ ही औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा न करने वाली शिक्षा प्रणाली ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जहां भारत औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल और पूंजी से काफी हद तक वंचित था। इसने देश को गंभीर नुकसान में डाल दिया, जिससे औपनिवेशिक काल के दौरान औद्योगीकरण लगभग असंभव हो गया। स्वतंत्रता के बाद, भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो अविकसित थी और आयात पर बहुत अधिक निर्भर थी, जिसमें सीमित औद्योगिक क्षमता और वित्तीय संसाधन थे। ब्रिटिश नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की आर्थिक चुनौतियों में अभी भी स्पष्ट हैं, जहां औद्योगिक देशों के साथ तालमेल बिठाने के प्रयासों को आर्थिक शोषण और बुनियादी ढांचे की उपेक्षा की विरासत ने बाधित किया था। निष्कर्ष रूप में, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां न केवल औपनिवेशिक युग के दौरान भारत के औद्योगिक विकास के लिए हानिकारक थीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए देश के आर्थिक विकास को भी पीछे धकेल दिया। जबकि भारत ने स्वतंत्रता के बाद से औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की विरासत इसके विकास पथ को प्रभावित करना जारी रखती है। इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना उन चुनौतियों को समझने के लिए आवश्यक है जिनका सामना भारत ने किया - और जिनका सामना वह अभी भी कर रहा है - एक आत्मनिर्भर औद्योगिक अर्थव्यवस्था विकसित करने के अपने प्रयासों में।

संदर्भ

1. चंद्रा, बिपन. (2000). स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष. नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स. ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का एक व्यापक विश्लेषण।

2. दत्त, रोमेश चंदर. (1901). प्रारंभिक ब्रिटिश शासन के तहत भारत का आर्थिक इतिहास. लंदन: लॉन्गमैन, ग्रीन एंड कंपनी. दत्त का काम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक शोषण की जांच करता है, जिसमें स्वदेशी उद्योगों के विनाश और ब्रिटिश नीतियों के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।
3. नौरोजी, दादाभाई. (1901). भारत में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन. लंदन: स्वान सोनेंशाइन. नौरोजी का मौलिक काम "धन की निकासी" के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, जो इस बात का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है कि कैसे भारत से धन निकाला गया और ब्रिटेन में स्थानांतरित किया गया, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न हुई।
4. रॉय, तीर्थकर. (2000). भारत का आर्थिक इतिहास 1857-1947. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. यह पुस्तक औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास का अवलोकन प्रदान करती है, जो व्यापार, उद्योग की संरचना और ब्रिटिश नीतियों के समग्र आर्थिक प्रभाव पर केंद्रित है।
5. लास्की, हेरोल्ड. (1940). भारत में ब्रिटिश साम्राज्य. लंदन: जॉर्ज एलन एंड अनविन लिमिटेड. लास्की का काम भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के राजनीतिक और आर्थिक परिणामों की पड़ताल करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास की भूमिका और भारतीय औद्योगीकरण के लिए इसकी सीमाएँ शामिल हैं।
6. थरूर, शशि. (2016). अंधकार का युग: भारत में ब्रिटिश साम्राज्य. नई दिल्ली: एलेफ बुक कंपनी. थरूर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत की आलोचना करते हैं, औपनिवेशिक एजेंडे के हिस्से के रूप में भारतीय संसाधनों के शोषण और औद्योगिक विकास को रोकने पर प्रकाश डालते हैं।
7. अजीज, के.के. (1993). भारत में ब्रिटिश विरासत. कराची: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और औद्योगीकरण पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों की जांच करती है।
8. दुबे, एच.बी., और श्रीनिवास, एम.एन. (1973). उपनिवेशवाद और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों और भारत के औद्योगीकरण और कृषि क्षेत्रों पर उनके हानिकारक प्रभाव पर एक विस्तृत अध्ययन।
9. बोस, सुगाता और जलाल, आयशा। (2004)। आधुनिक दक्षिण एशिया: इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। लंदन: रूटलेज। यह कार्य दक्षिण एशियाई इतिहास का एक व्यापक संदर्भ प्रदान करता है, जो इस क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है।
10. टॉमलिंग्सन, बी.आर. (1993)। राज की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: भारत में उपनिवेशवाद के उन्मूलन का अर्थशास्त्र। लंदन: मैकमिलन। यह पुस्तक ब्रिटिश राज के आर्थिक ढांचे और औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय औद्योगीकरण और विकास पर इसके प्रभावों की जांच करती है।
11. विपीन चन्द्रा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हि.मा.कार्या. निदे., 1995, नई दिल्ली
12. बी.एल. गोयल, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चन्द्र, 1981
13. द्विजेंद्र त्रिपाठी, 1991, कांग्रेस एंड दि इंडस्ट्रियलिस्ट (1885-1947), इन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया: ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, संपा. डी.त्रिपाठी
14. आदित्य मुखर्जी 1986, दि इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास : आस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डवलपमेंट इन दि कॉलोनिअल पीरियड, 1927-47, इन सिटुएटिंग इंडियन हिस्ट्री फॉर सर्वपल्ली गोपाल, संपा. एस. भट्टाचार्य एंड आर. थापर
15. बिपिन चन्द्र 1979, नेशनलिज्म एंड कॉलोनिअलिज्म इन मॉडर्न इंडिया
16. अली, एम. (2015) समाज के सबसे गरीब तबके का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण - भिखारीरू उत्तर प्रदेश, भारत का एक केस स्टडी, पृष्ठ संख्या 13.

17. अनूप कुमार शुक्ला, सी. एस. (2018) जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग और भूमि आवरण परिवर्तन, और ऊपरी गंगा नदी बेसिन में जल गुणवत्ता संबंध। जल विज्ञान. पृथ्वी प्रणाली. विज्ञान, पृष्ठ संख्या 22.
18. अशोक गुलाटी, पी. टी. (2016), उत्तर प्रदेश में कृषि का प्रदर्शन, पृष्ठ संख्या 209-215
19. गेडेस, ए. (2014) सिन्धु-गंगा के मैदान की जलोढ़ आकृति विज्ञानरू इसका मानचित्रण और भौगोलिक महत्व । ब्रिटिश भूगोलवेत्ता संस्थान, पृष्ठ संख्या 253-276 मानचित्र तैयार करने के लिए-जजचेरुधू कंजुंतंचमत.कमध् ।
20. जे. वेंकटेश्वरालु, वाई. आर. (1996) भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र शुष्क क्षेत्र का इतिहास,, पृष्ठ संख्या
21. खान, आर. एच. (2018) उत्तर प्रदेश, भारत में कृषि उत्पादन और उसके प्रदर्शन का अस्थायी विश्लेषण, करंट माइक्रोबायोलॉजी और एप्लाइड साइंसेज के इंटरनेशनल जर्नल, पृष्ठ संख्या 06.